गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 256
दि. 17.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

लाल किले की साजिश और कानून का शिकंजा: छह आरोपित न्यायिक हिरासत में

(जीएनएस)। दिल्ली का लाल किला केवल पत्थरों से बनी ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, संप्रभुता और गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसी प्रतीक के आसपास जब दहशत का विस्फोट हुआ तो उसकी गूंज केवल राजधानी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश के दिलो-दिमाग को झकझोर गई। उसी भयावह प्रकरण में अब न्याय की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले से जुड़े छह आरोपितों को 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना द्वारा सुनाया गया, जिसे जांच के लिहाज से निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। जिन छह लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उनमें डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद, जहीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ. आदिल अहमद, यासिर अहमद डार और डॉ. मुजम्मिल शकील शामिल हैं। एनआईए का दावा है कि ये सभी किसी न किसी रूप में उस आतंकी तंत्र का हिस्सा रहे, जिसने राजधानी के सबसे संवेदनशील इलाके में विस्फोट की साजिश रची। इससे पहले अदालत ने 14 जनवरी को यासिर अहमद डार को छोड़कर अन्य आरोपितों को 16 जनवरी तक एनआईए हिरासत में भेजा था, ताकि उनसे विस्तृत पूछताछ की जा सके और साजिश की परतें खोली जा सकें। हिरासत अवधि पूरी होने पर सभी को फिर अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश हुआ।

जांच एजेंसी के दस्तावेजों में सबसे अधिक चर्चा जहीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की है। श्रीनगर से गिरफ्तार इस युवक को लेकर एनआईए का कहना है कि वह तकनीकी रूप से बेहद प्रशिक्षित था और उसने ड्रोन में ऐसे परिवर्तन किए जिनका इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री पहुंचाने में किया जा सकता था। आरोप है कि कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट जैसी घातक प्रणाली तैयार करने की कोशिश भी उसी के निर्देशन में हुई। एजेंसी के अनुसार दानिश ने उमर-उन-नबी नामक सहयोगी के साथ मिलकर पूरी योजना को मूर्त रूप दिया और हमले की आधारभूमि तैयार की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजनीति विज्ञान का स्नातक यह युवक सामान्य जीवन से कट्टरता के रास्ते पर कैसे पहुंचा, यह आज भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर सवाल बना हुआ है।

तफ्तीश के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अक्टूबर 2024 में दानिश ने कुलगाम की एक मस्जिद में तथाकथित "डॉक्टर मॉड्यूल" के सदस्यों से मुलाकात की थी। यहीं से उसे आगे की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बाद में उसे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में ठहराया गया, जहां से साजिश के तार और मजबूत हुए। जांच एजेंसी का मानना है कि यह ठिकाना केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि योजनाओं को अंतिम रूप देने का केंद्र था। यहीं से तकनीकी उपकरण जुटाए गए, फंडिंग की व्यवस्था हुई और हमले की रूपरेखा तैयार की गई।

10 नवंबर 2025 की वह शाम आज भी दिल्ली के लिए किसी बुरे सपने जैसी है। लाल किला के पास खड़ी एक आई-10 कार अचानक धमाके से फट गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास का इलाका धुएं और चीख-पुकार से भर गया। इस आतंकी वारदात में 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 32 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में पता चला कि कार आमिर रशीद अली के नाम पर पंजीकृत थी और उसी के जरिए विस्फोटक सामग्री को लक्ष्य तक पहुंचाया गया। इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भीतर तक हिला दिया और तत्काल एनआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।

एनआईए की पड़ताल जैसे-जैसे आगे बढ़ी, साजिश का दायरा उतना ही बड़ा नजर आने लगा। एजेंसी का दावा है कि यह हमला अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि महीनों की तैयारी, ब्रेनवॉशिंग और संगठित नेटवर्क का परिणाम था। विभिन्न राज्यों में फैले संपर्क, डिजिटल माध्यमों से संवाद, विदेशी फंडिंग की आशंका और युवाओं को गुमराह करने की रणनीति—इन सबने मिलकर एक खतरनाक ढांचा खड़ा किया। यह भी सामने आया कि आरोपितों में कई पढ़े-लिखे और पेशेवर लोग शामिल हैं, जो समाज की मुख्यधारा का हिस्सा थे। इससे यह चिंता और गहरी हो जाती है कि शिक्षित वर्ग के भीतर कट्टर सोच किस तरह जड़ें जमा रही है।

अदालत में सुनवाई के दौरान एनआईए ने तर्क दिया कि अभी कई अहम कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। डिजिटल उपकरणों से मिले आंकड़ों की फॉरेंसिक जांच, फोन कॉल और इंटरनेट चैट के विश्लेषण, वित्तीय लेन-देन की पड़ताल तथा संभावित विदेशी संपर्क—ये सभी बिंदु बेहद संवेदनशील हैं। यदि आरोपितों को खुला छोड़ा गया तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का खतरा हो सकता है। अदालत ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, ताकि जांच निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़ सके।

यह प्रकरण केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि उस वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है जो देश के भीतर चल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल पुलिसिया कार्रवाई काफी नहीं। समाज को भी यह समझना होगा कि नफरत और कट्टरता के बीज कहां बोए जा रहे हैं। जिन युवाओं को विज्ञान, शिक्षा और विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वे किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरकर विनाश का रास्ता चुन लेते हैं—इस पर गहरा मंथन जरूरी है।

लाल किले के आसपास हुआ धमाका देश की आत्मा पर लगी चोट था। यही कारण है कि आम लोग इस मामले में त्वरित और कड़े न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार ने भी स्पष्ट संदेश दिया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दी गई है कि वे साजिश के हर सूत्रधार तक पहुंचें, चाहे वह देश के भीतर हो या बाहर।

अब सबकी निगाहें 13 फरवरी पर टिकी हैं, जब अदालत में अगली सुनवाई होगी। संभव है तब तक कुछ और खुलासे हों, नए नाम सामने आएं या साजिश की अंतरराष्ट्रीय परतें भी उजागर हों। लेकिन इतना तय है कि यह लड़ाई लंबी है और न्याय की राह आसान नहीं। फिर भी देश का कानून अपने कदम मजबूती से बढ़ा रहा है। लाल किले की धरती पर हुए इस अपराध को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, और न्याय की मशाल तब तक जलती रहेगी जब तक हर गुनहगार अपने अंजाम तक न पहुंच जाए।

दिल्ली 2025: 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी हमला

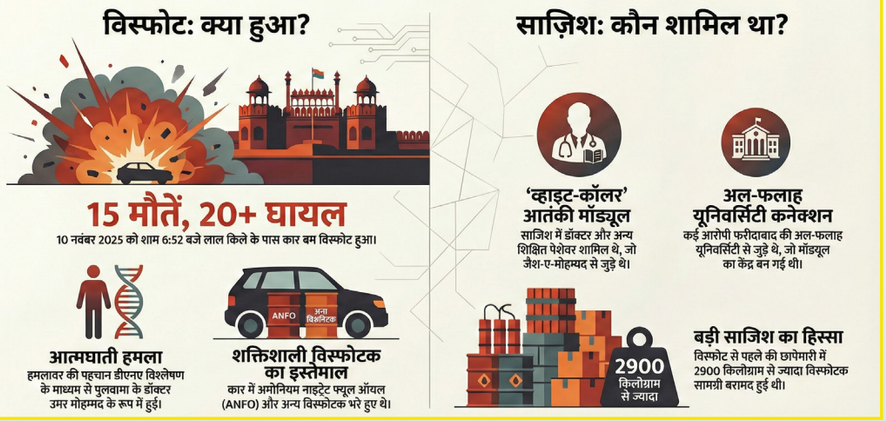

डिजिटल क्रांति की नई उड़ान, भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5जी बाजार

(जीएनएस)। भारत ने तकनीक और दूरसंचार के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाई है। देश में 5जी सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि डिजिटल भारत के उस सपने की मजबूत तस्वीर है, जिसे कुछ वर्ष पहले तक असंभव माना जाता था। इस मुकाम के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5जी उपभोक्ता बाजार बन गया है और इस सूची में केवल चीन ही उससे आगे है।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया मंच के माध्यम से यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत में 5जी तकनीक को अपनाने की रफ्तार वैश्विक स्तर पर सबसे तेज रही है। उन्होंने बताया कि देश के कोने-कोने में नेटवर्क विस्तार का काम युद्धस्तर पर चल रहा है और तेज इंटरनेट सेवाएं अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहीं। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक 5जी की पहुंच ने डिजिटल असमानता की खाई को तेजी से पाटना शुरू कर दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 5जी केवल तेज इंटरनेट का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने वाली तकनीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, परिवहन और मनोरंजन—हर क्षेत्र में इसके प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में वर्चुअल क्लासरूम अधिक प्रभावी हुए हैं, टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरदराज के मरीज बड़े अस्पतालों से जुड़ पा रहे हैं और किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म से मौसम व बाजार की सटीक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई डिजिटल इंडिया मुहिम का यह सबसे सशक्त अध्याय माना जा रहा है। संचार मंत्री ने कहा कि 5जी की यात्रा ने पैमाने और गति दोनों मामलों में नए वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। जिस तेजी से टावर लगाए गए, स्पेक्ट्रम का उपयोग हुआ और कंपनियों ने सेवाएं शुरू कीं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। आज देश के सैकड़ों शहरों में 5जी लाइव हो चुका है और प्रतिदिन नए इलाके इससे जुड़ रहे हैं।

दूरसंचार कंपनियां भी इस बदलाव को ऐतिहासिक मान रही हैं। उनके अनुसार उपभोक्ताओं का व्यवहार तेजी से बदला है। वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड आधारित सेवाएं और डिजिटल भुगतान पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। उद्योग जगत का कहना है कि 5जी के कारण स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ग्रामीण भारत में इसका असर और भी गहरा है। पहले जहां तेज इंटरनेट सपना था, वहां अब डिजिटल सेवा केंद्र, ऑनलाइन बैंकिंग और ई-गवर्नेंस रोजमर्रा का हिस्सा बन रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मोबाइल के जरिये मिलने लगा है। किसानों के लिए ड्रोन आधारित निगरानी, स्मार्ट सिंचाई और डिजिटल मंडी जैसे प्रयोग 5जी के कारण ही संभव हो रहे हैं।

हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नेटवर्क के लिए भारी बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता बड़े मुद्दे हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी मोर्चों पर ठोस नीति बनाई जा रही है। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने और सस्ते 5जी उपकरण उपलब्ध कराने पर भी काम चल रहा है ताकि आम आदमी तक इसका वास्तविक लाभ पहुंच सके। देश के लिए यह उपलब्धि केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है। 40 करोड़ 5जी उपभोक्ता इस बात का प्रमाण हैं कि भारत भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ चुका है।

राजधानी की सांसों पर फिर संकट, ग्रैप-3 की सख्ती लौटी

(जीएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली चादर में लिपट गई है और लोगों की सांसों पर नया संकट गहरा गया है। वर्ष 2026 में दूसरी बार हालात इतने बिगड़े हैं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण यानी ग्रैप-3 को लागू करना पड़ा। शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनसीआर के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौसम की स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हालात और चिंताजनक हो सकते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी की शाम चार बजे दिल्ली का एक्यूआई 343 दर्ज किया गया था, लेकिन महज चौबीस घंटों के भीतर यह बढ़कर 354 पर पहुंच गया। प्रदूषण के इस तेज उछाल ने प्रशासनिक एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दिनों हवा की गति बेहद कम है और तापमान में उतार–चढ़ाव के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ही ठहर जा रहे हैं। न तो हवा का पर्याप्त बहाव हो रहा है और न ही धूप इतनी तेज है कि प्रदूषण की परत छंट सके। यही वजह है कि स्मॉग की मोटी चादर राजधानी पर छाई हुई है और दृश्यता भी लगातार प्रभावित हो रही है।

ग्रैप-3 लागू होते ही कई तरह की पाबंदियां फिर से प्रभावी हो गई हैं। सबसे बड़ा असर वाहनों के संचालन पर पड़ा है। बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के चलने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है, जिससे लाखों वाहन मालिक सीधे प्रभावित होंगे। निर्माण और विध्वंस कार्यों को भी तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि धूल और मलबा प्रदूषण बढ़ाने के प्रमुख कारण माने जाते हैं। स्टोन क्रशर इकाइयों, हॉट मिक्स प्लांट और कंक्रीट बैचिंग प्लांट को भी बंद रखने को कहा गया है। इसके अलावा डीजल जनरेटर के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, केवल आपात सेवाओं को सीमित छूट दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और नगर निगमों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल और कचरा जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। आयोग ने साफ किया है कि ग्रैप-3 के साथ पहले से लागू चरण-1 और चरण-2 की सभी पाबंदियां भी जारी रहेंगी। इसका अर्थ है कि खुले में निर्माण सामग्री रखने, कोयला व लकड़ी जलाने, पुराने वाहनों के इस्तेमाल और औद्योगिक प्रदूषण पर पहले से लगी रोक भी यथावत प्रभावी रहेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाए। बढ़ते प्रदूषण का सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगियों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में खांसी, दमा और आंखों में जलन के मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह–शाम की सैर से बचने, मास्क का उपयोग करने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि वे बाहरी गतिविधियों को सीमित रखें। यदि एक्यूआई 400 के पार पहुंचता है तो प्राथमिक विद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद करने और दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण केवल स्थानीय कारणों से नहीं बढ़ता, बल्कि आसपास के राज्यों से आने वाला धुआं, वाहनों का अत्यधिक दबाव और औद्योगिक उत्सर्जन भी बड़ा कारण हैं। सर्दियों के मौसम में पराली जलाने की घटनाएं भले कम हो गई हों, लेकिन वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों की धूल स्थिति को लगातार बिगाड़ रही है। उन्होंने दीर्घकालिक नीति बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हर साल आपातकालीन कदम उठाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता।

व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने ग्रैप-3 के कारण होने वाली आर्थिक दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े लाखों मजदूरों की रोजी-रोटी पर फिर संकट आ गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कहना है कि पुराने वाहनों पर रोक से माल ढुलाई प्रभावित होगी और महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि लोगों की सेहत सर्वोपरि है और प्रदूषण कम करने के लिए कड़े फैसले लेना मजबूरी बन गया है।

सरकार और एजेंसियां भले ही लगातार दावे कर रही हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दिल्ली हर साल इसी चक्र में फंस जाती है। थोड़े सुधार के बाद फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। नागरिकों का कहना है कि जब तक सार्वजनिक परिवहन मजबूत नहीं होगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिलेगा और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वित योजना नहीं बनेगी, तब तक हालात बदलना मुश्किल है। फिलहाल राजधानी के लोग साफ हवा के लिए आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन मौसम के तेवर बता रहे हैं कि यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है।

बीज की शुद्धता से तय होगा किसानों का भविष्य

(जीएनएस)। देश के अन्नदाताओं को अब घटिया, नकली और मिलावटी बीजों के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार बीज क्षेत्र में दशकों पुराने कानून को बदलकर ऐसा मजबूत तंत्र खड़ा करने जा रही है, जिससे किसान के हाथ में पहुंचने वाला हर दाना भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब कोई भी व्यापारी या कंपनी किसानों को धोखा देकर मुनाफा नहीं कमा सकेगी। प्रस्तावित बीज अधिनियम 2026 के जरिए न केवल सख्त दंड का प्रावधान किया जाएगा, बल्कि देसी बीज उत्पादकों को नई ताकत भी दी जाएगी।

वर्तमान बीज अधिनियम 1966 के समय देश की कृषि व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। तब न तो बीजों का इतना बड़ा बाजार था, न निजी कंपनियों की इतनी दखल। समय के साथ कृषि का स्वरूप बदला, लेकिन कानून लगभग वहीं ठहरा रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि कई इलाकों में किसानों को घटिया बीज मिलने लगे, जिनसे न तो पैदावार होती थी और न लागत निकल पाती थी। कई बार किसान कर्ज में डूब गया, लेकिन दोषियों पर मामूली कार्रवाई ही हो सकी। मंत्री का कहना है कि पुराने कानून में दंडात्मक प्रावधान इतने कमजोर हैं कि गलत काम करने वालों में डर पैदा ही नहीं होता।

नया कानून इस तस्वीर को बदलने वाला है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत बीज बेचने वाले हर डीलर, कंपनी और आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर किसी बीज के कारण फसल खराब होती है, तो किसान को मुआवजा दिलाने की स्पष्ट व्यवस्था होगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने और कठोर सजा तक का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि जब तक बाजार में अनुशासन नहीं आएगा, तब तक किसान सुरक्षित नहीं हो सकता।

देश में पिछले कुछ वर्षों में बीज कारोबार अरबों रुपये का उद्योग बन चुका है। सैकड़ों निजी कंपनियां आकर्षक पैकिंग और बड़े दावों के साथ बीज बेचती हैं। कई बार विज्ञापनों में दिखाए गए नतीजे खेत तक पहुंचते ही हवा हो जाते हैं। किसान के पास न तो जांच की सुविधा होती है और न कानूनी लड़ाई लड़ने की ताकत। यही वजह है कि नया कानून उपभोक्ता यानी किसान को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि बीज की गुणवत्ता वही हो, जो पैकेट पर लिखी हो।

एक महत्वपूर्ण पहलू देसी बीजों को प्रोत्साहन देना भी है। आईसीएआर, कृषि विश्वविद्यालयों और पारंपरिक बीज संरक्षकों द्वारा विकसित किस्में अक्सर स्थानीय जलवायु के लिए ज्यादा अनुकूल होती हैं। लेकिन बाजार में विदेशी और हाइब्रिड बीजों के शोर में ये पीछे छूट जाती हैं। नए अधिनियम में देसी बीज उत्पादकों को बढ़ावा देने, उन्हें पंजीकरण में सहूलियत देने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की योजना है। इससे ग्रामीण स्तर पर बीज उत्पादन का नया तंत्र खड़ा हो सकता है। विदेश से आने वाले बीजों को लेकर भी सरकार सख्त रुख अपना रही है। कई देशों से आयातित बीज बिना पर्याप्त परीक्षण के बाजार में पहुंच जाते हैं, जिनसे स्थानीय फसलों पर विपरीत असर पड़ता है। अब हर आयातित बीज को कड़े वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरना होगा। उसकी उत्पादकता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरण पर प्रभाव की जांच के बाद ही बिक्री की अनुमति मिलेगी। यह कदम देश की जैव विविधता और किसानों की आय दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी माना जा रहा है।

कठुआ के जंगलों में सुरक्षा बलों का प्रहार, आतंक के तीन अड्डे नेस्तनाबूद

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले से सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी सफलता की खबर आई है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान के दौरान बिलावर क्षेत्र के घने जंगलों में आतंकियों के तीन ठिकानों का पता लगाकर उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर की गई और इसे इलाके में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार सात जनवरी से कामाड़ नाला, कलाबन और धनु परोल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध तत्व इन जंगलों को छिपने और गतिविधियों के संचालन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी आधार पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमें इलाके में उतारी गईं। घने जंगल, खड़ी पहाड़ियां और खराब मौसम के बावजूद जवानों ने लगातार अभियान जारी रखा।

तलाशी के दौरान एक स्थान पर छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद आतंकी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद इलाके की बारीकी से जांच की गई तो वहां एक ठिकाना मिला, जहां से एम-4 राइफल के खाली कारतूस, खाद्य सामग्री, कंबल, तिरपाल और रोजमर्रा के उपयोग का अन्य सामान बरामद हुआ। इससे स्पष्ट हुआ कि आतंकी लंबे समय से इस स्थान को सुरक्षित अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।

इसके बाद 16 जनवरी को अभियान का दायरा बढ़ाया गया और कलिखड़ तथा कलाबन क्षेत्र में दो और ठिकानों की पहचान की गई। इन स्थानों से भी बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई, जिन्हें आतंकियों ने छिपने और हमलों की तैयारी के लिए जमा किया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन ठिकानों के जरिये आसपास के इलाकों में बड़ी वारदातों की साजिश रची जा रही थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया।

एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने बताया कि पूरा अभियान आपसी तालमेल और पेशेवर रणनीति के तहत चलाया गया। उन्होंने कहा कि जिले की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने तक कार्रवाई जारी रहेगी। उनके अनुसार अभी भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।

स्थानीय लोगों ने सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि इन इलाकों में लंबे समय बाद सुरक्षा का भरोसा लौटा है। ग्रामीणों के मुताबिक पहाड़ी रास्तों पर अजनबी लोगों की आवाजाही से डर का माहौल बना रहता था, लेकिन अब प्रशासन की सक्रियता से स्थिति सुधर रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। विश्लेषकों का मानना है कि कठुआ और उसके आसपास के क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील रहे हैं, क्योंकि ये इलाके सीमा से जुड़े हैं और घने जंगल आतंकियों को छिपने का मौका देते हैं। ऐसे में लगातार चलाए जा रहे संयुक्त अभियान बेहद जरूरी हैं। हाल के महीनों में सुरक्षाबलों ने जिस तरह खुफिया तंत्र को मजबूत किया है, उससे आतंकी संगठनों के नेटवर्क पर लगातार चोट पड़ रही है।

संपादकीय

कॉलेज का कलेजा

दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने की कोशिशें उन्नीसवीं सदी के एक दूरदर्शी और परोपकारी सरदार दयाल सिंह मजीठिया जी की स्मृति और विरासत की घोर अवहेलना को ही दर्शाती हैं। यह कॉलेज उन्हीं के नाम पर दिल्ली में स्थापित और प्रतिष्ठित है। 'द ट्रिब्यून' और 'पंजाब नेशनल बैंक' के संस्थापक रहे सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष व समावेशी कॉलेज की स्थापना का स्वप्न साकार करना चाहा, जहां जनहित में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। उल्लेखनीय है कि दिल्ली स्थित इस संस्थान का समृद्ध इतिहास 1910 से तब शुरू होता है, जब मजीठिया जी के निधन के बारह वर्ष बाद लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आज कॉलेज प्रबंधन की ओर से दलील दी जा रही है कि एक ही नाम से डे कॉलेज और इवनिंग कॉलेज संचालित नहीं किए जा सकते हैं। यह कहना तार्किक नहीं लगता कि नाम बदलने से प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की सुविधाजनक स्थिति भी बन सकती है। वहीं दूसरी ओर, यह कॉलेज के कलेजे रूपी गरिमामय विरासत और जनभावनाओं को नजरअंदाज करने जैसा है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस बदलाव की कोशिशों के कानून पहलू भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। दरअसल, वर्ष 1978 में हस्तांतरण डीड की धारा 12, जिसके तहत ही दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू ने कॉलेज का अधिग्रहण किया था, में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 'संस्थान दयाल सिंह कालेज के नाम से ही जाना जाता रहेगा।' इस धारा का उल्लंघन करने की स्थिति में भूमि अधिकार छीनने और जबरन विस्थापन जैसी गंभीर कार्रवाई भी की जा सकती है। निश्चित रूप से इस तरह का जोखिम कोई भी जिम्मेदार प्रशासन हल्के में नहीं लेना चाहेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संकाय सदस्यों को सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर कॉलेज का नाम बदलने के प्रस्ताव की जानकारी तब मिली जब पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने वीर बाल दिवस के मौके पर इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी।

यहां उल्लेखनीय है कि दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज एक कालखंड की गरिमामय स्मृतियों को सहेजे हुए है। भारत मां के महान सपूत सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने अपने सारी संपत्ति समाज के लिये समर्पित कर दी थी। उन्होंने अपना जीवन एक स्वतंत्र प्रेस, उत्तर भारत में शिक्षा के प्रसार के लिये एक उच्चस्तरीय कॉलेज तथा जागरूकता के लिये पुस्तकालय की स्थापना के लिये लगाया। जिसका मकसद समाज में प्रगतिशील सोच विकसित करना और अज्ञानता को समाप्त करना ही था। ऐसे में एक पुनीत उद्देश्य के लिये स्थापित कॉलेज का नाम बदलने का प्रबंधनतंत्र द्वारा इस तरह का एकतरफा निर्णय विश्वविद्यालय के मूल सिद्धांत को ही कमजोर करता है। जिसका मूल उद्देश्य परामर्श और आम सहमति से कार्य करना होता है। इन कोशिशों के बीच कॉलेज के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने ऐसे किसी प्रयास का विरोध करने का फैसला किया है। कर्मचारी संघ द्वारा पारित प्रस्ताव में कॉलेज की पहचान और भविष्य को प्रभावित करने वाले इस कदम को लेकर असंतोष जताया गया है। छात्रों में भी इस बात को लेकर रोष देखा गया है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं होता, बल्कि सामूहिक स्मृति का संरक्षक भी होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भी महाविद्यालय का नाम बदलकर 'वंदे मातरम् महाविद्यालय ' रखने का प्रयास किया गया था। लेकिन यह प्रयास हितधारकों के विरोध के चलते सिरे नहीं चढ़ सका था। अब बदलाव की कोशिश करने वालों को पिछले असफल प्रयास को एक सबक के रूप में देखना चाहिए था। दिल्ली विश्वविद्यालय को ऐसे किसी प्रयास से पहले विचार विमर्श करने तथा चिंतन करने की आवश्यकता है। खासकर, ऐसे वक्त में जब एक महान व्यक्तित्व का नाम और साथ ही एक सदी से अधिक की शैक्षणिक और नैतिक विरासत दांव पर लगी हो।

दक्षिण में चुनावी बयार और भाषा की राजनीति

> 'जन नायकन' जहां सिनेमा के सुपरस्टार विजय को राजनेता के रूप में स्थापित करना चाहती है, वहीं 'पराशक्ति' साठ के दशक में चले हिंदी-विरोधी आंदोलन की उस आधारभूत राजनीति को उभारना चाहती है, जिसके सहारे द्रविड़ राजनीति ने राज्य से कांग्रेस को बाहर किया था। यह फिल्म अनायास ही नहीं बना ली गई है।

तमिलनाडु में इन दिनों दो फिल्में चर्चा का विषय हैं। एक है फिल्म अभिनेता से राजनेता बने विजय की 'जन नायकन' और दूसरी शिवकार्तिकेयन की 'पराशक्ति।' दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के सुपरस्टार विजय ने करीब डेढ़ साल पहले 'तमिषगा वेत्री कषगम' (टीवीके) नाम से पार्टी बनाकर राजनीति में प्रवेश किया है। दूसरी तरफ 'पराशक्ति' अपनी एंटी-हिंदी थीम के कारण चर्चित है। दोनों को फिल्म सेंसर बोर्ड की कुछ आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से 'जन नायकन' रिलीज़ नहीं हो पाई, जबकि 'पराशक्ति' करीब बीस बदलाव करके रिलीज़ हो गई है।

तमिल राजनीति में दोनों फिल्मों के गहरे निहितार्थ हैं। हालांकि, विजय पेरियार के रास्ते पर चलने का दावा करते हैं और राज्य की द्रविड़ पार्टियों की भाषा नीति के पक्षधर हैं, पर वे सत्तारूढ़ डीएमके के सामने चुनौती के रूप में उभर कर आना चाहते हैं। उनकी फिल्म की थीम जनता के बीच से उभर कर आए ऐसे ही नेता पर केंद्रित है। इसमें जनता के नायक की अवधारणा, विजय के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है।

तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा के कलाकारों का बोलबाला पचास के दशक से ही शुरू हो गया था। वहां की 'कटआउट' संस्कृति में 'आसमानी कद' के राजनेता सिनेमा के पर्दे से आए। तमिलनाडु शायद अकेला ऐसा राज्य है, जहां लगातार पांच मुख्यमंत्री सिनेमा जगत से आए। केवल कलाकारों की बात ही नहीं है, वहां की फिल्मों की स्क्रिप्ट में द्रविड़ विचारधारा को डालने का काम भी किया। 1952 की फिल्म 'पराशक्ति' ने द्रविड़ राजनीतिक संदेश जनता तक पहुंचाया था। इस फिल्म का स्क्रीनप्ले और संवाद के. करुणानिधि ने लिखे थे, जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके पहले सीएन अन्नादुरै ने भी कई फिल्मों की पटकथाएं लिखीं। जैमिनी गणेशन, एमजी रामचंद्र, जयललिता और अब विजय और कमलहासन परोक्ष या प्रत्यक्ष राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। रजनीकांत ने भी कुछ समय पहले कदम बढ़ाए थे, जो बाद में खींच लिए। अब जो 'पराशक्ति' रिलीज़ हुई है, वह 1952 वाली फिल्म का रीमेक नहीं है। इसके साथ कथित 'हिंदी-साम्राज्यवाद' के विरोध का राजनीतिक संदेश जुड़ा है। पुरानी 'पराशक्ति' जाति और सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर केंद्रित थी, जबकि नई 'पराशक्ति' साठ के दशक के हिंदी-विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

'जन नायकन' जहां सिनेमा के सुपरस्टार विजय को राजनेता के रूप में स्थापित करना चाहती है, वहीं 'पराशक्ति' साठ के दशक में चले हिंदी-विरोधी आंदोलन की उस आधारभूत राजनीति को उभारना चाहती है, जिसके सहारे द्रविड़ राजनीति ने राज्य से कांग्रेस को बाहर किया था। यह फिल्म अनायास ही नहीं बना ली गई है। इसकी थीम और रिलीज़ के समय को काफी गहराई से सोच-विचारकर तैयार किया गया है।

अगले तीन-चार महीनों में पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। इनमें असम और बंगाल के मसले दक्षिण के तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और केरल के मसलों से अलग हैं, जहां क्षेत्रीयता और भाषा की पृष्ठभूमि पिछले डेढ़-दो साल से तैयार की जा रही है। इसमें अब कर्नाटक को भी जोड़ सकते हैं, जहां हिंदी-विरोध की हवा कुछ देर से पहुंची है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर बड़े रोचक संवाद पढ़ने को मिल रहे हैं।

नई 'पराशक्ति' को लेकर एक दर्शक ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे यह फिल्म देखकर निराशा हुई, जिसमें एक उपराष्ट्रीयता को हथियार बनाकर राष्ट्रीय-एकता को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में फिल्म के एक समर्थक ने लिखा, हिंदी हमारे लिए विदेशी भाषा है। इसके जवाब में किसी ने लिखा, अंग्रेजी तो आपके घर में जन्मी है। एक और हैंडल में लिखा गया, कर्नाटक के लिए तेलुगु, तमिल, मलयालम विदेशी भाषाएं हैं। तेलुगु राज्यों के लिए कन्नड़, मलयालम, तमिल विदेशी भाषाएं हैं। तमिलनाडु के लिए तेलुगु, कन्नड़, मलयालम विदेशी भाषाएं हैं। पूरे दक्षिण को एक साथ क्लब करना बंद करो। कम से कम, तेलुगु राज्यों ने हिंदी का विरोध नहीं किया। हम हिंदी भी बोलते हैं।

दक्षिण के ही एक यूज़र ने लिखा, वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान तमिल के रूप में हो। उन्होंने तमिलों को द्रविड़ियन कहा, जो बड़ी पहचान है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नडिगा और मलयाली शामिल हैं, ताकि वे इसमें फिट हो सकें। एक यूज़र ने लिखा, उत्तर भारत वाले मुगलों और अंग्रेजों के हमलों का विरोध करते हैं, उसी तरह हम हिंदी के हमले का विरोध करते हैं। इस पर एक पाठक ने लिखा, हिंदी भारतीय भाषा है, क्या भारत के लोग अपने ही देश पर हमला करते हैं? भाषा और राष्ट्रीय एकता को लेकर देश के भीतर बहस हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, पर सोशल मीडिया की बहसें 'मॉडरेटेड' नहीं होतीं। उनमें अक्सर भावनाओं का अतिरेक होता है और शब्दों का ऊल-जुलूल इस्तेमाल होता है। पिछले एक साल से तमिलनाडु सरकार नई शिक्षा-नीति में तीन-भाषा सूत्र का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ज़रूरी नहीं है कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई हो। 22 भाषाओं की सूची में से कोई एक भाषा तीसरी भाषा के रूप में पढ़ी जा सकती है। तमिल लोगों को हिंदी से दुश्मनी या एलर्जी है तो उनके पास अन्य भाषाओं के विकल्प भी हैं। वे बांग्ला चुन सकते हैं, तेलुगु पढ़ सकते हैं, मलयालम चुन सकते हैं।

इस भाषा-युद्ध के अंतर्विरोध भी हैं। केरल विधानसभा ने पिछले अक्तूबर में एक विधेयक पारित किया था, जिसमें मलयालम को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था और सरकारी सेवाओं, न्यायपालिका सहित अन्य क्षेत्रों में इसके उपयोग की बात कही गई थी। इसमें कहा गया है कि केरल के सभी स्कूलों में मलयालम पहली भाषा के रूप में अनिवार्य होगी। राज्य में निर्मित या बिक्री के लिए लाए गए सभी उत्पादों पर लेबल मलयालम में भी होना चाहिए।

हालांकि, यह विधेयक अभी राज्यपाल के पास विचाराधीन है, पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे कर्नाटक की सीमा से लगे केरल के कासरगोड जिले में कन्नड़ भाषी लोगों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, यह विधेयक संविधान द्वारा प्रदत्त भाषा की स्वतंत्रता पर हमला है। सिद्धारमैया के अनुसार, कासरगोड भावनात्मक रूप से कर्नाटक का है, भले ही यह प्रशासनिक रूप से केरल का हिस्सा है। वे कर्नाटक के कन्नडा लोगों से कम नहीं हैं। उनके हितों की रक्षा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है।

ऐसी बातों से हैरत नहीं होती, क्योंकि राजनीति को नए विवादों की जरूरत है। ऐसी चिंताएं केरल के तमिलनाडु से लगे इलाकों की तमिलभाषी आबादी को लेकर व्यक्त की गई हैं। भाषा को लेकर ऐसी स्थितियां कई राज्यों की सीमाओं पर हैं। इनके हल जनता खुद खोज लेती है, पर राजनेता उन्हें भड़काते हैं। कुछ ऐसा ही पिछले दिनों महाराष्ट्र में देखने में आया, जहां स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन मसलों से राजनीति को अलग करें और व्यावहारिक हल खोजें। भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें अनेक भाषाओं की जानकारी लोगों को सबल ही बनाएगी, उनसे कुछ छीनेगी नहीं।

प्रेरणा

नवविचार से जन्म लेती राष्ट्र की समृद्धि

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का नाम केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है जिसने भारत को सपने देखना सिखाया। उनका मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी प्रयोगशील सोच और आम नागरिकों की रचनात्मक ऊर्जा में छिपी होती है। वे बार-बार कहते थे कि तरक्की ऊपर से थोपी नहीं जाती, वह नीचे से, समाज के भीतर से उगती है। यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ ले और देश के लिए कुछ नया करने का संकल्प ले, तो विकास की गति अपने आप तेज हो जाती है।

कलाम साहब युवाओं से विशेष लगाव रखते थे। उन्हें विश्वास था कि भारत की युवा शक्ति यदि सही दिशा में काम करे तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। वे चाहते थे कि लोग केवल नौकरी खोजने वाले न बनें, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बनें। इसी सोच के साथ वे लगातार ऐसे उपाय खोजते रहते थे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी उन्नति—तीनों को एक साथ जोड़ सकें। उनके लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं तक सीमित विषय नहीं था, बल्कि आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का साधन था।

एक अवसर पर उन्होंने देश के सामने जट्रोफा के वृक्ष लगाने का विचार रखा। यह सुझाव सुनकर कई लोग चकित रह गए, क्योंकि उस समय ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर ही अधिक चर्चा होती थी। कलाम ने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि जट्रोफा ऐसा पौधा है जो बंजर और अनुपयोगी जमीन पर भी उग सकता है। उसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है और विशेष देखभाल के बिना भी यह दशकों तक फल देता रहता है। इसके बीजों से निकलने वाला तेल डीजल में मिलाकर जैविक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार एक साधारण सा पौधा ऊर्जा संकट का समाधान बनने की क्षमता रखता है।

यह विचार केवल ईंधन उत्पादन तक सीमित नहीं था। इसके पीछे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा सपना छिपा था। देश में लाखों हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो खेती के लायक नहीं मानी जाती। यदि वहां जट्रोफा लगाया जाए तो वह भूमि भी आय का साधन बन सकती है। किसानों को अतिरिक्त कमाई मिलेगी, गांवों में छोटे उद्योग विकसित होंगे और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होगा। कलाम का सपना था कि भारत तेल आयात पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादक बने।

उनकी बातों में गहरी वैज्ञानिक समझ के साथ मानवीय संवेदना भी होती थी। वे जानते थे कि केवल तकनीक से देश नहीं बदलता, लोगों की भागीदारी से बदलता है। इसलिए उन्होंने इस अभियान को जनआंदोलन का रूप देने पर जोर दिया। कई राज्यों ने उनकी प्रेरणा से बड़े पैमाने पर जट्रोफा रोपण शुरू किया। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों ने इसके बेहतर बीज और प्रसंस्करण तकनीक विकसित करने का काम संभाला। धीरे-धीरे यह पहल केवल भारत तक सीमित न रहकर अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों तक भी पहुंची, जहां भारतीय अनुभव से सीख लेकर इसी दिशा में काम शुरू हुआ।

कलाम साहब की सोच की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे समस्याओं को अवसर में बदल देते थे। जहां लोग बंजर जमीन को बेकार समझते थे, वहां उन्होंने संभावनाओं का संसार देखा। जहां दूसरे लोग ऊर्जा संकट से घबराते थे, वहां उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर समाधान खोजा। उनका मानना था कि प्रकृति मनुष्य की शत्रु नहीं, सबसे बड़ी सहयोगी है। यदि हम उसका सम्मान करते हुए तकनीक विकसित करें तो विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं। वे अक्सर कहते थे कि सपने वही नहीं जो सोते समय दिखते हैं, सपने वे हैं जो सोने नहीं देते। जट्रोफा का अभियान भी ऐसे ही जागते सपने का परिणाम था। उन्होंने देशवासियों को यह भरोसा दिलाया कि सामान्य नागरिक भी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। जरूरत केवल ईमानदार प्रयास और दूरदृष्टि की है। उनके लिए नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करना था।

आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ईंधन संकट से जूझ रही है, तब कलाम का यह दृष्टिकोण और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि भविष्य स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का है। यदि भारत ने समय रहते इस दिशा में कदम बढ़ा दिए तो वह विश्व का मार्गदर्शक बन सकता है। उनका सपना था कि गांवों से निकलने वाली शक्ति ही देश को महाशक्ति बनाएगी।

कलाम साहब के जीवन से यह सीख मिलती है कि सच्ची तरक्की केवल आर्थिक आंकड़ों में नहीं मापी जाती। असली प्रगति वह है जो आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाए, किसानों को सम्मान दे, युवाओं को अवसर दे और प्रकृति को सुरक्षित रखे। उन्होंने हमेशा ज्ञान को सेवा से जोड़ा। उनके अनुसार वैज्ञानिक का कर्तव्य केवल खोज करना नहीं, बल्कि उस खोज को समाज के हित में उपयोगी बनाना है।

जट्रोफा की पहल इसी विचारधारा का प्रतीक है। यह बताती है कि यदि सोच सकारात्मक हो तो छोटी सी पहल भी बड़े बदलाव का आधार बन सकती है। कलाम चाहते थे कि हर भारतीय अपने भीतर छिपे वैज्ञानिक और नवोन्मेषी मन को पहचाने। वे मानते थे कि देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिकों का आत्मविश्वास है। उनका संदेश आज भी उतना ही जीवंत है कि भारत का भविष्य दूसरों की नकल से नहीं, अपनी मौलिक सोच से बनेगा। जब खेतों, प्रयोगशालाओं और उद्योगों में एक साथ नवाचार होगा, तभी वास्तविक विकास होगा। डॉ. कलाम ने हमें यह राह दिखाई कि सपने देखने का साहस रखो, उन्हें पूरा करने की मेहनत करो और देश को अपने से बड़ा मानो। यही दृष्टिकोण किसी भी राष्ट्र को समृद्धि के शिखर तक ले जा सकता है और यही उनके जीवन का सबसे अनमोल संदेश है।

पीड़ितों का शास्त्र न बन जाए उमर-शरजील की हिरासत

छह साल पहले राजधानी दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी हिस्से के जाफराबाद और मौजपुर में हुए दंगों पर राजनीति थम नहीं रही है। राजनीति तब भी खूब हुई, जब 23 फरवरी 26 फरवरी 2020 के बीच हुए दंगों का घाव बिल्कुल हरा था। इस बार इन दंगों पर राजनीति की वजह पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से आया एक आदेश है, जिसमें इन दंगों के पांच आरोपियों गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी गई है। इस आदेश को लेकर राजनीति ही नहीं हो रही, प्रकारांतर से देश की सबसे बड़ी अदालत भी निशाने पर है। सर्वोच्च अदालत ने इन दंगों के आरोपी शरजील इमाम उमर खालिद को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर इन दोनों आरोपियों के पक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई। मनमोहन सिंह की सत्ता और कांग्रेस के आंख के तारे रहे जेएनयू के पूर्व छात्र रहे एक बड़े पत्रकार ने इन दोनों आरोपियों को देश का प्रखर बुद्धिजीवी बताते हुए उन्हें जमानत ना दिए जाने पर आश्चर्य जताया।वामपंथी वैचारिकी की एक खासियत है। वह अपने पक्ष में अकादमिक तर्क गढ़ने में माहिर रही है। अपने लिहाज के तथ्यों को चुनकर उसके हिसाब से वह तर्क गढ़ने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही अपनी वैचारिकी के लोगों को पीड़ित दिखाने में वह हमेशा आगे रहती रही है। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में वामपंथी वैचारिकी उसी तरह से उमड़ पड़ी है। वह दोनों के बारे में यह राय बनाने की भरपूर और प्रभावी कोशिश कर रही है कि दोनों दंगाई नहीं, दंगे के शातिर षड्यंत्रकारी नहीं, बल्कि वे प्रखर बुद्धिजीवी हैं। वामपंथी वैचारिकी यह साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि दोनों चूंकि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से हैं, और चूंकि केंद्र में हिंदुत्ववादी सत्ता है। इसलिए अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों को दबाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात यह विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्ववादी सत्ता के इशारे पर अदालत मुस्लिम समुदाय के निर्दोष बुद्धिजीवियों को बलि का बकरा बना रही है। यह विमर्श खड़ा करके वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात दरअसल दंगाईयों को पीड़ित के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प यह है कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को नकारने के लिए जहां सर्वोच्च न्यायालय को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं बाकी पांच आरोपियों को जमानत दिए जाने के आदेश को जबरदस्ती नेपथ्य में धकेलने की कोशिश की जा रही है। दो लोगों को जमानत ना मिलने को, पांच लोगों को जमानत मिलने की प्रक्रिया के सामने पक्षपाती दिखाया जा रहा है। पांच आरोपियों को मिली जमानत को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा करके सर्वोच्च अदालत ने कोई एहसान नहीं किया है।

वामपंथी वैचारिकी के इस विमर्श का पूरा मकसद यह भुलाना है कि 2020 के दिल्ली दंगे हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं थे। इस विमर्श का लक्ष्य यह भी भुलाना है कि इन दंगों में अधिसंख्य हिंदू समुदाय के लोग मारे गए थे। इस विमर्श का यह भी मकसद है कि इन दंगों के दौरान आईबी के मासूम अधिकारी अंकित शर्मा की हुई हत्या को सामान्य अपराध दिखाने की कोशिश हो रही है। इन दंगों में आधिकारिक रूप से 53 लोग मारे गए थे। दंगा खत्म होने के बाद कई लाशें नाले में बहती मिलीं। जिस तरह उस दौरान दंगे के एक आरोपी आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन के घर पत्थर, हथियार और बड़ी-सी गुलेल मिली, उससे तो यही साबित होता है कि दिल्ली के ये दंगे हिंदू समाज को सबक सिखाने की मुस्लिम समाज के कुछ दंगाइयों की कोशिश थी। इन दंगों की टाइमिंग को भी भुलाना आसान नहीं है। जब ये दंगे हुए थे, उसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का भारत दौरा हुआ था। इन दंगों के जरिए कोशिश यह भी की गई थी कि दंगा के षड्यंत्रकारियों का मकसद ट्रंप की भारत यात्रा को निरस्त कराना, भारतीय राज व्यवस्था को बदनाम करना और इसके जरिए भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना था। इसमें किंचित वे कामयाब भी हुए। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में उठती आवाजों का प्रतिकार भी जरूरी है। इन आवाजों की पोल खोलना भी जरूरी है। राष्ट्रवादी धारा के प्रबुद्धजन वामपंथी विमर्श के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जिस तरह कभी वामपंथी वैचारिकी के अगुआओं को देश की मौजूदा व्यवस्था में राजकीय तवज्जो मिल रहा है, उससे प्रखर राष्ट्रवादी वैचारिकी किंचित परेशान भी है और दुखी भी। इसलिए जैसा इस वामपंथी विमर्श का प्रतिकार होना चाहिए, उस स्तर का प्रतिकार नहीं हो पा रहा है। यह तो भला हो कि हिंदुत्ववादी मानस इन दिनों बेहद सचेत हो चुका है। निश्चित तौर पर इसकी वजह मुस्लिम तुष्टिकरण की हकीकत का सामने आना तो है ही, केंद्रीय सत्ता में मोदी की अगुआई में हिंदुत्वादी ताकतों का प्रभावी बनना भी है। दिल्ली दंगों को लेकर नए विमर्श गढ़ने की कोशिशें होती रहेंगी। जरूरत यह है कि इसका लगातार उचित प्रतिकार तो होते ही रहे, हिंदुत्व विरोधी नैरेटिव के खिलाफ आक्रामक राष्ट्रवादी विमर्श लगातार उठता रहे। इसी अंदाज में होना यह चाहिए कि दिल्ली दंगों को लेकर बार-बार यह कहा जाना चाहिए कि ये हिंदुओं के खिलाफ खुराफाती और शांति विरोधी मुस्लिम सिरफिरों के सुनियोजित अपराध थे। जिसमें 53 लोगों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर हिंदु थे। दो सौ से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भी बताने की कोशिश होनी चाहिए कि घायलों में भी ज्यादातर हिंदू ही थे। इसकी भी बार-बार चर्चा होनी चाहिए कि इन दंगों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय की ही दुकानों और हिंदू समुदाय के ही मकानों को लक्ष्य बनाकर नुकसान पहुंचाया गया। यह भी बताने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए कि इन दंगों का एक मकसद तत्कालीन नागरिकता संबंधी कानून में संसद द्वारा किया गया संसोधन भी था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी दुष्प्रचार भी था। लगातार ऐसा जवाबी विमर्श खड़ा होता रहा तो मुस्लिम समुदाय के शांति विरोधी और अपराधी और दंगाई समर्थक वर्ग की मंशा का खुलासा करना आसान होगा। लगातार जारी ऐसे विमर्श की वजह से हिंदुत्व विरोधी ताकतें जहां एक्सपोज होंगी, वहीं उनके खिलाफ आम मानस उठ खड़ा होगा।

अभियान

सरयू की लहरों पर जीवित होगी रामकथा की धरोहर

अयोध्या केवल एक नगर नहीं, बल्कि भारतीय आस्था, संस्कृति और इतिहास की जीवित चेतना है। सरयू नदी के किनारे बसी यह पावन नगरी सदियों से श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के नौकाविहार को एक नए और अनूठे अनुभव में बदलने की पहल की है, जिसमें सरयू की लहरों पर तैरते हुए यात्री केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं देखेंगे, बल्कि रामनगरी की अनसुनी कथाओं और परंपराओं से भी रूबरू होंगे। इस योजना के तहत नाविक केवल चप्पू चलाने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि प्रशिक्षित मार्गदर्शक और कथावाचक की भूमिका निभाएंगे, जो यात्रियों को अयोध्या की आत्मा से जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने घोषणा की कि अयोध्या में नौकाविहार के दौरान नाविक तीर्थयात्रियों को प्राचीन मंदिरों, घाटों, परंपराओं और लोकविश्वासों से जुड़ी कहानियां सुनाएंगे। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे केवल नाव संचालन तक सीमित न रहें, बल्कि सांस्कृतिक दूत के रूप में उभरें। मंत्री के अनुसार अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरयू में नौकायन के प्रति लोगों का आकर्षण भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया था कि इस अनुभव को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और ज्ञानवर्धक बनाया जाए।

पर्यटन विभाग ने 15 से 17 जनवरी तक तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 55 नाविकों को आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार के कौशल सिखाए गए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नाविकों को डिजिटल भुगतान प्रणाली, स्टोरीटेलिंग, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और पर्यटक व्यवहार जैसे विषयों में दक्ष बनाना है। आज के समय में जब अधिकांश यात्री ऑनलाइन भुगतान का उपयोग करते हैं, तब नाविकों का डिजिटल रूप से सशक्त होना जरूरी है। इसी तरह आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जीवन रक्षक तकनीकों का भी अभ्यास कराया गया।

अयोध्या का नौकाविहार अब केवल एक सैर नहीं रहेगा, बल्कि यह सांस्कृतिक यात्रा का रूप लेगा। सरयू के किनारे बने राम की पैड़ी, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की अपनी-अपनी कथाएं हैं। अब नाविक इन स्थलों के पास से गुजरते हुए उनके महत्व, उनसे जुड़ी लोकगाथाओं और धार्मिक मान्यताओं को सरल भाषा में यात्रियों को सुनाएंगे। इससे बाहर से आने वाले पर्यटक अयोध्या को केवल इमारतों के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा के रूप में समझ सकेंगे।

मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान और राज्य आपदा मोचन बल के सहयोग से चल रहे इस कार्यक्रम का लक्ष्य पर्यटन को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर संस्कृति और सुरक्षा से जोड़ना है। सरकार का मानना है कि जब स्थानीय लोग पर्यटन से सीधे जुड़ते हैं, तभी उसका वास्तविक लाभ समाज तक पहुंचता है। नाविक पीढ़ियों से सरयू के साथ जीवन जीते आए हैं। उनके अनुभवों में अयोध्या की वह स्मृतियां छिपी हैं जो किताबों में नहीं मिलतीं। इस पहल से वही स्मृतियां अब श्रद्धालुओं तक पहुंचेंगी।

मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि जल पर्यटन का तेजी से विस्तार हो रहा है और इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इसलिए जरूरी है कि नाविक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हों। सुरक्षित नौकायन, यात्रियों से संवाद का तरीका, भीड़ प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को भी इस प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। सरकार चाहती है कि अयोध्या आने वाला हर यात्री यहां से सुखद और सुरक्षित अनुभव लेकर लौटे।

यह पहल केवल पर्यटन बढ़ाने की योजना नहीं, बल्कि नाविक समाज के सशक्तीकरण का भी माध्यम है। अब तक उनका काम केवल नाव चलाना माना जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में उन्हें सम्मानजनक पहचान मिलेगी। जब वे प्रशिक्षित कथावाचक और गाइड के रूप में कार्य करेंगे, तो उनकी आय के साधन भी बढ़ेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। सरकार की मंशा है कि वे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के सशक्त प्रतिनिधि बनें।

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सरयू आरती, दीपोत्सव और अन्य आयोजनों ने इस नगरी को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिया है। ऐसे में नौकाविहार का नया स्वरूप यात्रियों के लिए अतिरिक्त आकर्षण बनेगा। कल्पना कीजिए, जब शाम के समय सरयू की लहरों पर तैरती नाव में बैठा यात्री नाविक के मुख से रामायण काल की कथाएं सुनेगा, तो वह अनुभव किसी पुस्तक पढ़ने से कहीं अधिक जीवंत होगा।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण संरक्षण भी है। प्रशिक्षण के दौरान नाविकों को सरयू की स्वच्छता, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने और नदी पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील रहने की सीख दी गई है। पर्यटन तभी टिकाऊ हो सकता है जब प्रकृति का सम्मान किया जाए। सरकार चाहती है कि अयोध्या का विकास आध्यात्मिक मूल्यों के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखे।

धीरे-धीरे यह मॉडल उत्तर प्रदेश के अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों में भी लागू किया जाएगा। काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट जैसे स्थानों पर भी जल पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यदि हर जगह नाविक स्थानीय इतिहास और लोकसंस्कृति के वाहक बनें, तो पूरा प्रदेश एक खुला सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बन सकता है।

अयोध्या की पहचान सदैव से मर्यादा, करुणा और लोककल्याण से जुड़ी रही है। नौकाविहार की यह नई पहल उन्हीं मूल्यों का आधुनिक विस्तार है। जब यात्री सरयू में नौका पर बैठकर नाविक के मुख से रामराज्य की कथाएं सुनेंगे, तो उनके मन में केवल पर्यटन का आनंद नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव की अनुभूति भी जागेगी।

सरकार की यह योजना बताती है कि विकास केवल इमारतें बनाने से नहीं होता, बल्कि लोगों के कौशल और संवेदनाओं को जगाने से होता है। नाविक अब अयोध्या की पहचान के जीवित सेतु बनेंगे। उनकी आवाज में बसी कथाएं आने वाली पीढ़ियों तक रामनगरी की आत्मा को पहुंचाएंगी। इस तरह सरयू की लहरों पर बहती हर नाव केवल पानी का सफर नहीं करेगी, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की अविरल धारा को भी आगे बढ़ाएगी।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सफर की नई करवट: आज पटरी पर उतरेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत

(जीएनएस)। भारत की रेल यात्रा आज एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय पूर्वी भारत दौरे के दौरान देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलने वाली यह आधुनिक ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को तेज, सुरक्षित और पहले से कहीं अधिक आरामदेह बनाने का वादा लेकर आ रही है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल और असम में दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का भी शुभारंभ होगा, जो पूर्वी क्षेत्र की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएंगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार 17 जनवरी को मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, जहां रेल और सड़क अवसंरचना से जुड़ी लगभग 3,250 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसी कार्यक्रम में मालदा टाउन स्टेशन से वर्चुअल माध्यम द्वारा हावड़ा से कामाख्या के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर को रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित होगी, आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस रहेगी और पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में करीब ढाई घंटे कम समय में दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय का मानना है कि इससे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच आवाजाही को नई गति मिलेगी तथा पर्यटन और व्यापार दोनों को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल एक ट्रेन के शुभारंभ तक सीमित नहीं है। 18 जनवरी को हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रस्तावित है। इनमें सड़क सुधार, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। बालागढ़ में आधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान पोर्ट की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस बंदरगाह के निर्माण से अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, माल ढुलाई का खर्च घटेगा और कोलकाता सहित आसपास के शहरों की सड़कों पर यातायात का बोझ कम होगा। सरकार इसे गंगा आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

रेल क्षेत्र में विस्तार को और गति देते हुए प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से सात अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना करेंगे। ये ट्रेनें न्यू जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और मालदा जैसे शहरों को सीधे बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों से जोड़ेंगी। इससे कामगारों, विद्यार्थियों और छोटे कारोबारियों को विशेष लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों के संचालन से पूर्वी भारत के लाखों यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक लंबी दूरी की सेवा उपलब्ध होगी, जो क्षेत्रीय असमानता को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

असम प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सरोकारों से भी जुड़ा रहेगा। गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में आयोजित बोडो समुदाय के भव्य उत्सव बागुरुम्बा द्वौ 2026 में वे भाग लेंगे, जहां दस हजार से अधिक कलाकार पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन पूर्वोत्तर की समृद्ध लोक परंपराओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा देने का प्रयास है। सरकार का मानना है कि सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने से क्षेत्र में सामाजिक एकता मजबूत होती है और विकास योजनाओं को जनस्वीकृति मिलती है।

दौरे का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है। नागांव जिले के कालियाबोर में प्रधानमंत्री 6,950 करोड़ रुपये की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। 86 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग पार करते समय हाथियों और गैंडों की दुर्घटनाओं की खबरें आती रही हैं। ऊंचा मार्ग बनने से जानवरों को निर्बाध आवाजाही मिल सकेगी और इंसान तथा प्रकृति के बीच टकराव कम होगा। इसी अवसर पर गुवाहाटी से रोहतक और डिब्रूगढ़ से लखनऊ के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के बीच सीधा संपर्क सुदृढ़ होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में ब्लॉक के कारण ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। रतलाम, 16 जनवरी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के गोरखपुर–गोंडा रेलखंड में तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित

ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:-

निरस्त ट्रेनें –

गाड़ी संख्या 05053 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल जो पूर्व में 13 फरवरी 2026 तक निरस्त थी, उसे अब बढ़ाकर 27 मार्च 2026 तक निरस्त किया गया है।

गाड़ी संख्या 05054 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर स्पेशल जो पूर्व में 14 फरवरी 2026 तक निरस्त थी, उसे अब बढ़ाकर 28 मार्च 2026 तक निरस्त किया गया है।

शॉर्ट टर्मिनेशन /आंशिक रूप से निरस्तीकरण :-

गाड़ी संख्या 22921 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस जो पूर्व में 08 फरवरी 2026 तक बलरामपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जा रही थी, 29 मार्च 2026 तक बलरामपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

गाड़ी संख्या 22922 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस जो पूर्व में 10 फरवरी 2026 तक बलरामपुर स्टेशन से शॉर्ट ऑरिजिनेट की जा रही थी, 31 मार्च 2026 तक बलरामपुर स्टेशन से शॉर्ट ऑरिजिनेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन संचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

जनसंपर्क विभाग
रतलाम मंडल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस संपन्न

मुख्यमंत्री की लोगों की प्रस्तुतियों को सुनकर उनके जिला स्तर पर त्वरित और ईमानदार समाधान के लिए अधिक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करने पर ताकीद

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- फील्ड विजिट को प्राथमिकता देकर सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मॉनिटरिंग करें
- ओनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटिशन तथा इफेक्टिवनेस के आधार पर समग्र जिले के कामकाज के लिए आह्वान
- सरकार आपके साथ है ; सही व्यक्ति परेशान न हो और गलत व्यक्ति किसी को परेशानी न पहुंचा सके, इसके लिए सूझ-बूझ से बिना किसी डर के अच्छे और नेक कार्यों के लिए कलेक्टर जिला टीम का नेतृत्व करें

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को राज्य के जिला कलेक्टरों को लोगों की प्रस्तुतियां सुनकर उनके त्वरित और प्रामाणिक समाधान के लिए जिला स्तर पर अधिक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करने की ताकीद की है। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में प्रस्तुतियां लेकर आने वाले व्यक्ति की समस्या को समझकर उसे सहायता देने की संवेदनशीलता से ही लोगों का भरोसा और विश्वास अर्जित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि जिला स्तर पर ही समाधान संभव हो सके ऐसे प्रश्नों के लिए लोगों को सरकार या विभागों तक न आना पड़े और स्थानीय स्तर पर ही उनका समाधान त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी रूप से हो ।

गांधीनगर में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों को फील्ड विजिट को प्राथमिकता देकर सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मोनिटरिंग करने के सुझाव दिए। उन्होंने कलेक्टरों से ओनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटिशन तथा इफेक्टिवनेस; इन प्रमुख आधारों पर पूरे जिले के कामकाज का नेतृत्व करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों से कहा कि जिले के प्रमुख के रूप में जो दायित्व उन्हें मिला है, वह जन सामान्य की समस्या के निराकरण की जिम्मेदारी निभाते हुए वहन करने का एक बड़ा अवसर है।

मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि राज्य में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के कारण अब विकास कार्यों में धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे संजोगों में जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे विकास कार्य तेजी से और गुणवत्तापूर्ण हों, इसके लिए जिला टीम का नेतृत्व करते हुए कलेक्टर उचित निगरानी रखें।

श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से टीम वर्क के साथ तथा आपस में चर्चा करते हुए मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि परिपत्रों- नियमों का अलग-अलग अर्थघटन न हो और लोगों को अपने कार्यों में सरलता रहे; इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदारीपूर्वक कार्यरत रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके साथ है और सही व्यक्ति परेशान न हो तथा गलत व्यक्ति किसी को परेशानी न पहुंचा सके; इस उद्देश्य से सूझ-बूझ के साथ बिना किसी डर के अच्छे और नेक कार्यों के लिए जिला टीम का नेतृत्व कलेक्टरों को करना है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती स्वस्थ जीवनशैली के लिए अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती का मिशन प्रारंभ किया है। जिला कलेक्टरों से अपने-अपने जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर इस मिशन को सफल बनाने का भी आह्वान किया।

राजस्व राज्य मंत्री श्री संजय सिंह महिडा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित यह कॉन्फ्रेंस राजस्व विभाग के सर्वग्राही कामकाज को और अधिक गति प्रदान करेगा। उन्होंने जिला कलेक्टरों को जनप्रतिनिधियों की प्रस्तुतियों पर उचित कार्रवाई करने, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण में तेजी लाने तथा जिला स्तर पर फीडबैक मैकेनिज्म को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के सुझाव दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑनलाइन कार्यों के लिए पोर्टल्स का समय-समय पर समीक्षा करने पर भी समर्थन दिया।

इस बैठक में राजस्व राज्य मंत्री ने नई गठित तहसील मुख्यालयों पर लोगों को त्वरित सेवाएं मिलती रहे इसके लिए सरकारी कार्यालयों को शीघ्र कार्यरत करने तथा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आगामी समय में जिला वार समीक्षा बैठकों के आयोजन के सुझाव भी दिए।

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्व सरलीकरण के लोक हितकारी कदम उठाए हैं। इनका लाभ अंतिम स्तर तक पहुंचे; इसके लिए जिला कर्मयोगियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देने का कार्य जिला कलेक्टर अपने हाथ में लें।

अपर मुख्य सचिव ने यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर तहसील स्तर पर इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के पदों को स्वीकृति दी है, जिससे भूमि से जुड़े मामलों की लंबित संख्या कम होगी। इस दिशा में कलेक्टरों को विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, वरिष्ठ सचिवगण, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, जिला कलेक्टर तथा राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

इस एक दिवसीय सम्मेलन में विशेष रूप से आईओआरए/ई-धारा, आईआरसाएमएस, डीसीएलआर/एएलटी के लंबित केसों की समीक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा-मंथन किया गया।

उत्तर रेलवे में ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। रतलाम, 16 जनवरी। उत्तर रेलवे अंबाला मंडल के अंतर्गत डाउसनी स्टेशन यार्ड में प्वाइंट नवीनीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है—

1.19 जनवरी एवं 24 जनवरी 2026 को हरिद्वार से चलने वाली ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन हरिद्वार से 90 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

2.09 फरवरी 2026 को योग नगरी ऋषिकेश से चलने वाली ट्रेन संख्या 22660 योग नगरी ऋषिकेश–तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश से 90 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन संचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

जनसंपर्क विभाग
रतलाम मंडल

दक्षिण पूर्व रेलवे में ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। रतलाम, 16 जनवरी। दक्षिण पूर्व रेलवे में ब्लाक के कारण पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है—

1.15 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी 2026 एवं 05 फरवरी 2026 को अजमेर से चलने वाली ट्रेन संख्या 08612 अजमेर–संतरागाछी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर टोरी–बरकाकाना–मूरी मार्ग से परिवर्तित मार्ग से होकर चलेगी।

2.19 जनवरी, 26 जनवरी 2026 एवं 02 फरवरी 2026 को संतरागाछी से चलने वाली ट्रेन संख्या 08611 संतरागाछी–अजमेर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर मूरी–बरकाकाना–टोरी मार्ग से परिवर्तित मार्ग से होकर चलेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन संचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

जनसंपर्क विभाग
रतलाम मंडल

पोस्टल शिपमेंट पर निर्यात प्रोत्साहन का 15 जनवरी 2026 से विस्तार - एमएसएमई और ई-कॉमर्स निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा: फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन

(जीएनएस)। नई दिल्ली : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के ड्यूटी ड्रॉबैक, रोडटेप और आरओएससीटीएल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोस्टल माध्यम से किए गए निर्यात पर निर्यात प्रोत्साहन का विस्तार करने के फैसले का स्वागत किया है, जो 15 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने इस कदम को प्रगतिशील और लंबे समय से प्रतीक्षित बताया और कहा कि यह छोटे निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों को समान अवसर प्रदान करके एमएसएमई और ई-कॉमर्स निर्यात को काफी मजबूत करेगा, जो पोस्टल चैनलों पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा, लेनदेन लागत कम करेगा और पोस्टल निर्यात को एक मजबूत प्रोत्साहन देगा, जो सीमा पार ई-कॉमर्स का एक उभरता हुआ चालक है। लाभों को लागू करने के लिए, सीबीआईसी ने अधिसूचना संख्या 07/2026–सीमा शुल्क (एनटी) और परिपत्र संख्या 01/2026–सीमा शुल्क के माध्यम से पोस्टल निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 में संशोधन किया है, ये दोनों 15 जनवरी 2026 को जारी किए गए थे।

श्री रल्हन ने आगे बताया कि ये उपाय ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक सुधारों के पूरक हैं, जिसमें विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रावधान, पोस्टल निर्यात का एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण, आईजीएसटी रिफंड का स्वचालन, हब एंड स्पोक मॉडल और देश भर में 1,000 से अधिक डाक निर्यात केंद्र शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि पोस्टल शिपमेंट पर निर्यात प्रोत्साहन का विस्तार निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक ई-कॉमर्स परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करने में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

आपदा एवं दुर्घटना प्रबंधन तैयारियों का आकलन करने हेतु अंकलेश्वर स्टेशन पर मॉक ड्रिल

(जीएनएस)। वडोदरा रेल मंडल द्वारा आज सूरत - वडोदरा रेल खंड के अंकलेश्वर स्टेशन पर आपदा एवं दुर्घटना प्रबंधन तैयारियों का आकलन करने हेतु एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में कुल 98 रेलवे कर्मचारियों और 25 राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस सम्बन्ध में बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों के सभी रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों की सतर्कता और तैयारियों की जांच करना था। असली इमरजेंसी के दौरान रिस्पॉन्स टाइम कम करने और इंसानी गलतियों को रोकने के लिए समय-समय पर ऐसी मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मॉक ड्रिल के दौरान प्रातः लगभग 10:43 बजे एक परिकल्पित दुर्घटना के तहत यह स्थिति बनाई गई कि अंकलेश्वर की ICD साइडिंग से मुंबई मंडल स्थित JNPT साइडिंग जा रही एक मालगाड़ी का एक लोडेड वैगन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसके साउथ ट्रॉली के सभी पहिए पटरी से उतर गए तथा कुछ अन्य ट्रैक मैन घायल हो गए। उन्होंने बताया किघटना की जानकारी मिलते ही तत्परता दिखाते हुए वडोदरा से एक्सिडेंट रिलीफ़ मेडिकल इक्विपमेंट (ARME) तथा एक्सिडेंट रिलीफ़ ट्रेन (ART) एवं उधना से एक्सिडेंट रिलीफ़ ट्रेन (ART) तुरंत अंकलेश्वर भेजी गई। साथ ही वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके अन्य वरिष्ठ अधिकारिओं के साथ तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुए।

अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की आपातकालीन तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय तथा राहत कार्यों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना था। ड्रिल के दौरान प्राथमिक उपचार, भीड़ नियंत्रण, संचार व्यवस्था, संरक्षा उपाय तथा राहत गतिविधियों का विस्तृत अनुकरण किया गया।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई- निविदा सूचना

निम्नलिखित स्टोर कार्य के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (स्टोर), रतलाम, पश्चिम रेलवे द्वारा ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा संख्या: 83257321, दिनांक 13.01.2026. कार्य का नाम:** Provision of isolation switch for starring battery in power car as per RDSO modification sheet no. RDSO/PE/MS/AC/0086-2022 (Rev.0) or latest. The works includes supply, installation, testing and commissioning of isolation disconnector switch with fuse of approved make. List of material required in 1 Set Power Cars (1 Power car having 2 nos. D.A. Set) in above modification :- 1. Switch disconnecting fuse (SDF) 2 pole 315A 415V insulation suitable for 690 volt with 315A 415V breaking capacity minimum 100KA rating fuse and metallic cover, the switch disconnector of make L&T (CK910070009 ? SF94234), Siemens (3KX8345-4AC-3KL8331-2UA00- 3NA33520RC), ABB or Schneider or similar / better ? 02 Nos. 2. Copper Cable 120Sq.mm. as per RDSO Specification No. ELRS/ SPEC/ELC/0019. (Rev.-1) ? 32 Mtr. 3. Fuse Link SF 94234 315A ? 04 Nos. 4. Conduit as per RDSO Specification ? RDSO/PE/SPEC/AC-0138 2009 (Rev 1) for 120 Sq.mm. copper cable (NW-29) ? 32 Mtr. 5. Gland ? 04 Nos. 6. Control Cable Length ? 50 Mtr. Approx. [**Warranty Period:** 30 Months after the date of delivery] [**Inspection Agency:** TPI, **Stage Insp. :** No, Stages : 0] [**UVAM Linking:**] **Item Type:** Goods (supply). **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 70,96,774.88/-. **निविदा दस्तावेज़ की लागत:** 0 (Zero). **बयाना राशि जमा:** ₹ 1,41,940.00/-. **ऑफर की वैधता (दिन):** Within 90 days thereafter. **ई-निविदा दस्तावेज़ जमा करने के लिए समापन का समय और तारीख:** 04-FEB-26, 11:00 hrs. **ई-निविदा खोलने का समय और तारीख:** 04-FEB-26, 11:30 hrs. निविदा को ई-निविदा पोर्टल **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन देखा जा सकता है और प्रस्ताव उसी ई-निविदा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

DE/15/1/414

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

नवसारी मनपा के बाहरी क्षेत्रों में 112 करोड़ रुपये के खर्च से बनने वाले जलापूर्ति एवं ड्रेनेज नेटवर्क से 25 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार शहरीकरण को गति देने के साथ-साथ नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार शहरों के विस्तार के साथ ही नए शामिल होने वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति, ड्रेनेज पाइपलाइन, सड़क एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसके अंतर्गत हाल ही में नवसारी महानगर पालिका ने 112 करोड़ रुपए की जलापूर्ति और ड्रेनेज परियोजना कार्यान्वित की है। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2025 को नवसारी महानगर पालिका का गठन किया गया था, जिसमें पहले के नवसारी विजलपोर नगर पालिका क्षेत्र के साथ 4 निकटवर्ती गांवों एरु, धारागीरी, दांतेज और हांसापोर को शामिल किया गया। शहर के इन बाहरी इलाकों में शुद्ध पेयजल और ड्रेनेज की लाइनों के अभाव के कारण पीने के पानी और ड्रेनेज की गंभीर समस्या थी। इन समस्याओं के स्थायी हल के लिए नवसारी महानगर पालिका द्वारा इन क्षेत्रों में लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत से एक नया जलापूर्ति और ड्रेनेज नेटवर्क बनाया जा रहा है।

- नवसारी में नए ड्रेनेज और जलापूर्ति नेटवर्क से पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मिलेगी राहत
- गुजरात सरकार का जल प्रबंधन के कार्यों से छोटे शहरों को समस्याओं से मुक्त करने का अर्बन विजन

112 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले नए ड्रेनेज नेटवर्क से 25 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे

इस परियोजना के अंतर्गत महानगर पालिका द्वारा चरणबद्ध तरीके से नई पानी और ड्रेनेज की पाइपलाइनें, ओवरहेड टंकी और भूमिगत सम्प, ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी आधुनिक ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे 25,000 से अधिक स्थानीय नागरिकों को पेयजल और गंदे पानी की निकासी की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। विशेषकर, बच्चों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी अंत आएगा। नवसारी में जलापूर्ति और नया ड्रेनेज नेटवर्क केवल ढांचागत सुविधाओं में ही सुधार नहीं करेगा, बल्कि यह शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। नवसारी मनपा क्षेत्र में शामिल किए गए चार गांवों में सड़क, लाइट, ड्रेनेज और पानी के नए नेटवर्क के अलावा उद्यान और तालाबों का विकास कर विहार धाम का निर्माण, सिविक सेंटर और सफाई के लिए डस्टबिन वितरण का भी आयोजन किया जा रहा है। नवसारी महानगर पालिका के आयुक्त श्री देव चौधरी ने इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "नए साल में नवसारी महानगर पालिका शहर में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। जिसमें ड्रेनेज, सड़कें, स्टॉर्म वाटर और पानी की व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसी उद्देश्य से शहर में शामिल किए गए चार गांवों में ड्रेनेज, पानी और स्टॉर्म वाटर का समग्र नेटवर्क बिछाने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में इन चार गांवों में ड्रेनेज और जलापूर्ति का काम किया जाएगा। यह परियोजना निर्धारित समयरेखा के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है, जिससे लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी और उनकी सुख-सुविधा में वृद्धि होगी।"

गुजरात की विकास यात्रा में मील का पत्थर बना 'शहरी विकास वर्ष'

वर्ष 2005 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार 'शहरी विकास वर्ष' मनाने की शुरुआत की थी और शहरी विकास के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की थीं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस विकास यात्रा को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि उन्होंने 20 वर्ष बाद, 2025 को एक बार फिर 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

पश्चिम रेलवे द्वारा 26 जनवरी, 2026 से मुंबई उपनगरीय खंड में और 12 एसी लोकल ट्रेनों की शुरुआत,एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 109 से बढ़कर 121

(जीएनएस)। यात्रियों के बीच बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा सोमवार, 26 जनवरी, 2026 से मुंबई उपनगरीय खंड में एसी लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 12 नई एसी लोकल सेवाओं की शुरुआत के साथ एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या अब 109 से बढ़कर 121 हो जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एसी लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतः यात्रियों की सुविधा के लिए तथा भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे पर मौजूदा नॉन-एसी 12 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों के स्थान पर 12 अतिरिक्त एसी लोकल सेवाएँ शुरू की जा रही हैं। ये सभी सेवाएँ सप्ताह के सभी दिनों में एसी सेवाओं के रूप में परिचालित होंगी। लोकल ट्रेनों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात कुल 1406 लोकल सेवाएँ यथावत रहेंगी, जिनमें से 121 सेवाएँ एसी लोकल ट्रेन सेवाएँ होंगी। श्री विनीत ने आगे बताया कि शुरू की जा रही 12 और एसी लोकल ट्रेनों में से 6 ट्रेनें अप दिशा में और 6 ट्रेनें डाउन दिशा में हैं। अप दिशा में, विरार – चर्चगेट और गोरेगांव – चर्चगेट के बीच 2-2 ट्रेनें तथा बोरीवली – चर्चगेट और भायंदर – चर्चगेट के बीच एक-एक ट्रेन है। इसी तरह, डाउन दिशा में, चर्चगेट – विरार और चर्चगेट – गोरेगांव के बीच 2-2 ट्रेनें तथा चर्चगेट – भायंदर और चर्चगेट – बोरीवली के बीच एक-एक ट्रेन है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में 107 दिव्यांगजनों को 1.16 करोड़ रुपए की साधन सहायता का वितरण किया

▸▸ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजना तथा जेटको और पीजीवीसीएल के सीएसआर कार्यक्रम के तहत एलिम्को निःशुल्क दिव्यांग उपकरण सहायता वितरण कैंप आयोजित

▸▸ राज्य सरकार ने गत पांच वर्षों में 4 लाख से अधिक दिव्यांगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर 820 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं : केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया

▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने की संवेदनशील पहल की : कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में बड़ा काम किया

▸▸ दिव्यांगजनों के लिए वरदान बने दिव्याशा केंद्र

▸▸ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए गांधीनगर में 316 करोड़ रुपए के खर्च से एथलीट्स हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण हो रहा है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय खेलों में अधिक मेडल जीत सकें

▸▸ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'सशक्त दिव्यांगजन यानी सशक्त भारत' विजन के साथ गत 10 वर्षों में दिव्यांग कल्याण योजनाओं के खर्च में तीन गुना वृद्धि हुई

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को भावनगर में दिव्यांग उपकरण सहायता वितरण शिविर के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने दिव्यांगों का जीवन आसान और उन्नत बनाने के लिए दिव्यांगजनों के हित में अनेक निर्णय किए हैं। भावनगर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता योजना (एडिप योजना) और गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेटको) और पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत एलिम्को और भावनगर जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क दिव्यांग साधन-उपकरण सहायता वितरण कैंप का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक ही दिन में एक साथ 1017 दिव्यांगजनों को 1.16 करोड़ रुपए की साधन सहायता वितरित करने के इस कार्यक्रम को दिव्यांग कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता करार दिया। मुख्यमंत्री ने भावनगर और बोटाद जिले में 15 दिनों तक कैंप आयोजित कर 2600 से अधिक दिव्यांगजनों को 3.51 करोड़ रुपए के 4800 से अधिक साधनों का निःशुल्क वितरण कर उनकी आत्मनिर्भरता का अहम कार्य करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया और उनकी टीम को बधाई दी। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के दो सार्वजनिक उपक्रमों जेटको और पीजीवीसीएल की भी सीएसआर के तहत इस साधन वितरण में योगदान देने के लिए सराहना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में पिछले पांच वर्ष में 4 लाख से अधिक दिव्यांगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर 820 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। इतना ही नहीं, दिव्यांगों को प्रमाण पत्र के लिए बार-बार मेडिकल चेकअप कराने की मुश्किलों से भी मुक्ति मिली है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने के निर्णय से दिव्यांगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब 60 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधितों को संत सूरदास योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे योजनाओं का लाभ आसानी से मिलने के कारण दिव्यांगजन आत्मसम्मान से जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में दिव्यांगों का जीवन बदला और उन्हें नए अवसर प्रदान किए हैं, इस बात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में बड़ा कार्य किया है। इस अभियान के कारण देश में सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं स्थापित की गई हैं और ईज ऑफ लिविंग से उनका जीवन आसान बना है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की 'प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र' के निर्माण की पहल की चर्चा करते हुए कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 300 दिव्याशा केंद्र बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 100 तो कार्यरत हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए भी श्री मोदी ने योजनाबद्ध कार्यपद्धति अपनाई है। इस बारे में उन्होंने कहा कि गांधीनगर में 316 कोरड़ रुपए की लागत से पैरा एथलीटों के लिए हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण हो रहा है। इस सेंटर में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वे आने वाले समय में आयोजित होने वाले विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक मेडल जीत सकें। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में दिव्यांगजनों के शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी और उद्योगों में समान भागीदार बनाने की मंशा व्यक्त की।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अनेक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। दिव्यांगजनों के लिए सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं। बोटाद और भावनगर जिले में लगभग 2700 दिव्यांगजनों का परीक्षण किया गया था। भावनगर जिले में शिहोर और पालीताणा तथा बोटाद जिले में तीन कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिनमें 825 दिव्यांगजनों को कुल 121.20 लाख रुपए मूल्य के 1577 साधन वितरित किए गए।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। एडिप योजना के तहत लाखों दिव्यांगजनों को निःशुल्क आधुनिक सहायक साधन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत 11 वर्षों में दिव्यांगजनों को साधन-सहायता के लिए लगभग 18 हजार से अधिक कैंपों का आयोजन कर 31 लाख से अधिक दिव्यांगजनों तक सहायता पहुंचाई गई है।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि 'दिव्यांग' शब्द की भावनात्मक अभिव्यक्ति और दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्थाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिव्यांगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए जो संवेदनशील पहले की थी, उसका फल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दिव्यांग साधन सहायता कार्यक्रमों के जरिए अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी विनम्रता, निष्कपटता और संवेदनशील कार्य शैली के माध्यम से गुजरात में एक मजबूत नेतृत्व स्थापित किया है। उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणादायी बना है। उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों की प्रशंसा की।

श्री वाघाणी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां सीएसआर फंड का उचित उपयोग समाज के हित में करने के लिए आगे आ रही हैं। दिव्यांगजनों को साधन सहायता मिलने से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का शुभकामना संदेश पढ़ा गया।

भावनगर कलेक्टर डॉ. मनीष कुमार बंसल ने स्वागत भाषण दिया जबकि जिला विकास अधिकारी श्री हनुल चौधरी ने आभार व्यक्त किया। एलिम्को कंपनी के महाप्रबंधक श्री विवेक द्विवेदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा देते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर भावनगर के प्रभारी मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, महापौर श्री भरतभाई बारड़, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजूभाई राबड़िया, उप महापौर श्रीमती मोनाबेन पारेख, विधायक सर्वश्री सेजलबेन पंड्या, भीखाभाई बारैया, शंभुनाथ टुंडिया, गौतमभाई चौहाण, शिवाभाई गोहिल, केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री रवि शंकर, अग्रणी श्री कुमारभाई शाह और दिग्विजयसिंह गोहिल सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

अहमदाबाद मण्डल पर मण्डल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की चतुर्थ बैठक का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल में दिनांक 16.01.2026 को मण्डल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की चतुर्थ बैठक मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में आयोजित की गई। बैठक के प्रारम्भ में मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए उनके-अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए। समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अहमदाबाद मण्डल में चल रही विभिन्न गतिविधियों एवं विकासात्मक परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं में निरंतर सुधार करना तथा यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाना मण्डल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं और आगामी समय में मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर और अधिक आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री त्यागी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मण्डल की प्रमुख उपलब्धियों एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद, साबरमती एवं भुज स्टेशनों का मेजर रीडेवलपमेंट कार्य प्रगति पर है, जिनमें साबरमती एवं भुज स्टेशनों का कार्य उन्नत चरण (advance stage) में है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास "अमृत स्टेशन योजना" के अंतर्गत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि गेज परिवर्तन एवं अन्य आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यों में तेजी लाई गई है। हाल ही में आंबलियासन–विजापुर तथा मोटी–विजापुर रेलखंड का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है और इस खंड का सीआरएस निरीक्षण भी सम्पन्न हो गया है। शीघ्र ही इस सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

बैठक के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित रेल समस्याओं, ट्रेनों के ठहराव, ट्रेनों का विस्तार, ट्रेनों का स्टोपेज प्रदान करने, नई ट्रेन सेवा शुरू करने एवं अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज बनाने तथा नई परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन तथा स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। मण्डल रेल प्रबंधक ने प्रस्तुत विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्यवाही का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर समिति के सदस्य सर्वश्री राकेश कुमार जैन,हिंगोरभाई रबारी, जामाभाई देसाई, भगवानभाई एच.पटेल, भगवानदास के.पटेल, जितेन्द्र कुमार लेउवा, संजयभाई पटेल, दिलीपभाई पंड्या, किशोर ठाकुर, क्षितीश शाह, मुकेशकुमार ठाकर, अरविन्दभाई नायक, अनिकुमार पटेल, आर पी शर्मा, अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा, अपर मण्डल रेल प्रबंधक विकास गढ़वाल एवं मण्डल के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे तथा बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अवैध वॉकी-टॉकी बिक्री: अमेजन, फ्लिपकार्ट मीशो और मेटा पर लगे करोड़ों के जुर्माने

(जीएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने डिजिटल बाजार में अवैध उपकरणों की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाते हुए देश की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को आर्थिक दंडित किया है। यह कार्रवाई बिना वैध अनुमति और तकनीकी स्वीकृति के वॉकी-टॉकी उपकरणों की बिक्री को रोकने के उद्देश्य से की गई है। प्राधिकरण ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक मार्केटप्लेस) और मीशो पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो और मास्कमैन टॉय पर 1-1 लाख रुपये का दंड निर्धारित किया गया, जिससे कुल जुर्माना 44 लाख रुपये हो गया।

जांच के दौरान यह सामने आया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 16,970 ऐसे वॉकी-टॉकी उपकरण सूचीबद्ध थे, जो निर्धारित तकनीकी मानकों और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बाद सीसीपीए ने 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया, जिनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स, मीशो, जियोमार्ट, चिमिया, टॉक प्रो, मास्कमैन टॉयज, ट्रेडइंडिया, इंडियामार्ट, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज, वरदानमार्ट और कृष्णा मार्ट शामिल हैं।

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे पर्सनल मोबाइल रेडियो (पीएमआर) उपकरणों की बिक्री को बढ़ावा दे रहे थे, जो लाइसेंस-मुक्त निर्धारित फ्रीक्वेंसी बैंड के बाहर संचालित होते थे। नियमों के अनुसार इन उपकरणों के लिए 'उपकरण प्रकार अनुमोदन' (ईटीए) प्रमाणन अनिवार्य है। सीसीपीए ने पाया कि इनमें से अधिकांश उपकरणों के पास यह प्रमाणपत्र नहीं था।

प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे भविष्य में किसी भी उत्पाद की सूचीबद्धता से पहले तकनीकी और वैधानिक मानकों की पूरी जाँच करें। इससे उपभोक्ताओं के हितों और राष्ट्रीय नियमों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मीशो, मेटा, चिमिया, जियोमार्ट और टॉक प्रो ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है, जबकि अन्य कंपनियों के भुगतान की प्रक्रिया अभी लंबित है।

यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और दूरसंचार नियमों के उल्लंघन के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई। विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल मार्केट में ऐसी निगरानी आवश्यक है, क्योंकि अवैध उपकरण उपभोक्ताओं की सुरक्षा और रेडियो संचार प्रणाली की विश्वसनीयता दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं।

सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि जुर्माने के साथ-साथ कंपनियों को नियमित निगरानी और उत्पाद प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। इससे डिजिटल बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को मानक एवं सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध होंगे। यह कदम सरकार की ओर से उपभोक्ताओं की सुरक्षा और ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूत करता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के जुर्माने और सख्तीपूर्ण कदम ई-कॉमर्स कंपनियों को भविष्य में नियमों का पालन करने और अवैध उत्पादों को प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध न करने के लिए प्रेरित करेंगे। डिजिटल बाजार में विश्वास बहाल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं को ऐसे उपकरणों से होने वाले संभावित खतरे से बचाया जाए और ई-कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की भूमिका केवल बिक्री तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचीबद्ध उत्पाद राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और तकनीकी नियमों के अनुरूप हों। इस मामले में सीसीपीए का कड़ा रुख यह संदेश देता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को कानून से ऊपर नहीं रहने दिया जाएगा।

इस कार्रवाई के बाद डिजिटल बाजार में अन्य कंपनियों और विक्रेताओं को चेतावनी भी मिल गई है। भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी तेज हो सकती है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को भी जागरूक करने के प्रयास बढ़ाए जाएंगे, ताकि वे केवल प्रमाणित और सुरक्षित उत्पादों का ही उपयोग करें।

इस पूरे मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि डिजिटल उपभोक्ता सुरक्षा के लिए नियामक संस्थाएं सतर्क हैं और अवैध बिक्री को रोकने के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेंगी।

क्रूड ऑयल वायदा 83 रुपये तेज: सोना वायदा में 31 रुपये और चांदी वायदा में 104 रुपये का सुधार

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 40110.56 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 108912.9 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 33023.16 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38970 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 149028.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 40110.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 108912.9 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 38970 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2688.48 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 33023.16 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 142589 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 143296 रुपये और नीचे में 142400 रुपये पर पहुंचकर, 143121 रुपये के पिछले बंद के सामने 31 रुपये या 0.02 फीसदी की तेजी के संग 143152 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 248 रुपये या 0.21 फीसदी औंधकर 116000 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 10 रुपये या 0.07 फीसदी औंधकर 14532 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 142415 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 142950 रुपये और नीचे में 142002 रुपये पर पहुंचकर, 6 रुपये या 0 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 142856 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 143131 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 143595 रुपये और नीचे में 142700 रुपये पर पहुंचकर, 143406 रुपये के पिछले बंद के सामने 14 रुपये या 0.01 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 143420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 287127 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 292865 रुपये और नीचे में 285513 रुपये पर पहुंचकर, 291577 रुपये के पिछले बंद के सामने 104 रुपये या 0.04 फीसदी बढ़कर 291681 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 471 रुपये या 0.16 फीसदी की मजबूती के साथ 293892 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 341 रुपये या 0.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 293881 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में 3391.98 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 10.6 रुपये या 0.81 फीसदी घटकर 1297.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता जनवरी वायदा रु.1.3 या 0.41 फीसदी औंधकर 316.55 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.55 फीसदी औंधकर 316.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी की नरमी के साथ 191.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3470.22 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5340 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5438 रुपये और नीचे में 5314 रुपये पर पहुंचकर, 83 रुपये या 1.55 फीसदी बढ़कर 5430 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 86 रुपये या 1.61 फीसदी की तेजी के संग 5430 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 285.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 292 रुपये के दिन के उच्च और 283.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 283.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.4 रुपये या 1.91 फीसदी की बढ़त के साथ 288.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 5.5 रुपये या 1.94 फीसदी की बढ़त के साथ 288.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 970 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.2 रुपये या 0.23 फीसदी की मजबूती के साथ 976.5 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11675.90 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 21347.26 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2843.61 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 290.18 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 23.71 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 234.47 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 753.97 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2697.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20822 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 79399 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26839 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 400953 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 45330 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 13916 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 38721 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 98732 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22393 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 48959 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 38201 पॉइंट पर खूलकर, 39030 के उच्च और 37820 के नीचले स्तर को छूकर, 56 पॉइंट बढ़कर 38970 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 36.9 रुपये की बढ़त के साथ 267.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.4 रुपये की बढ़त के साथ 12.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 147000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 241 रुपये की गिरावट के साथ 639 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 295000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1682.5 रुपये की गिरावट के साथ 13189 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7.79 रुपये की गिरावट के साथ 25.72 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.2 रुपये की गिरावट के साथ 3.3 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 55.6 रुपये की गिरावट के साथ 213.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.85 रुपये की गिरावट के साथ 12.85 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 107.5 रुपये की गिरावट के साथ 786 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 285000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 855.5 रुपये की गिरावट के साथ 11816.5 रुपये हुआ।

तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.52 रुपये की बढ़त के साथ 29.06 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 15 पैसे की नरमी के साथ 0.65 रुपये हुआ।